भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2676
जिसका उत्तर सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकिंग और ऋण स्थिरता

†2676. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गैर-निष्पादित आस्तियों और पूंजी पर्याप्तता के रुझान सहित वर्तमान में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता की स्थिति क्या है;

(ख) क्या हालिया ऋण प्रतिबंधों और बाजार की चिंताओं ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा खुदरा कर्जदारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय ढांचे की स्थिरता से समझौता किए बिना ऋण का पर्याप्त और सस्ता प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले कुछ वर्षों में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए प्रमुख बैंकिंग सुधारों, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 4आर रणनीति (एनपीए को पारदर्शी रूप से पहचानना, समाधान और वसूली, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण और वित्तीय प्रणाली में सुधार) शामिल हैं, ने ऋण अनुशासन को मजबूत किया है, तनाव की पहचान और समाधान में सुधार किया है, जिम्मेदारी से उधार देने में सक्षम बनाया है और बैंकों में अभिशासन बढ़ाया है।

इन सुधारों के साथ-साथ वित्तीय समावेशन की पहल, प्रौद्योगिकी को अपनाना, बैंकों का समामेलन और प्रबंधन में सुधार तथा बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के उपायों ने बैंकों को संकट से उबरने और अपनी वित्तीय स्थिति और लचीलेपन में उल्लेखनीय सुधार करने में मदद की है।

इसके अलावा, उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज) सुधार एजेंडा के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सेवा वितरण, डिजिटल सक्षमता, पारदर्शिता और बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से ग्राहक-केंद्रित पहलों की एक श्रृंखला शुरू की है। आरबीआई द्वारा निर्धारित बेसल III पूंजी और विवेकपूर्ण मानदंडों के कार्यान्वयन से पूंजी बफर को मजबूती मिली है, जोखिम प्रबंधन में सुधार हुआ है और बैंकों का समग्र लचीलापन बढ़ा है। आरबीआई की 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई के मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट के परिणामों ने भी प्रतिकूल मैक्रोइकॉनॉमिक झटकों के प्रति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लचीलेपन की पुष्टि की है। दिनांक 30.9.2025 के आरबीआई के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार:

(क) परिसंपत्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है—

(i) एससीबी का सकल एनपीए अनुपात मार्च-15 में 4.28% (3.23 लाख करोड़ रुपये) और मार्च-18 में 11.18% (10.36 लाख करोड़ रुपये) के शीर्ष स्तर से घटकर सितंबर-25 में 2.05% (4.18 लाख करोड़ रुपये) के नए बहु-दशकीय निम्न स्तर पर आ गया।

(ii) एससीबी के निवल एनपीए मार्च-15 में 2.31 लाख करोड़ रुपये (3.13%) और मार्च-18 में 5.20 लाख करोड़ रुपये (5.94%) के उच्चतम स्तर से घटकर सितंबर-25 में रिकॉर्ड निचले स्तर 0.94 लाख करोड़ रुपये (0.47%) पर आ गया है।

(ख) एससीबी के प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में मार्च-15 में 49.31% से बढ़कर सितंबर-25 में 93.23% की सुदृढ़ वृद्धि के साथ लचीलापन बढ़ा है।

(ग) एससीबी का जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के साथ, जो 430 बीपीएस से सुधरकर मार्च-15 में 12.94% से बढ़कर सितंबर-25 में 17.24% हो गया है, पूंजी पर्याप्तता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 में शेयरधारकों को 27,830 करोड़ रुपये का कुल लाभांश (भारत सरकार का हिस्सा 18,013 करोड़ रुपये) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरधारकों को घोषित लाभांश 34,990 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा 22,699 करोड़ रुपये) था।

(ड.) व्यापक सुधारों के कार्यान्वयन के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे बाजार से पूंजी (इक्विटी और बांड दोनों के रूप में) जुटाने की उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक) के दौरान बाजार से 5.24 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है।

(च) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एससीबी ने 4.01 लाख करोड़ रुपये का अब तक का उच्चतम कुल निवल लाभ दर्ज किया है। पीएसबी ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपये का अब तक का उच्चतम कुल निवल लाभ दर्ज किया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों के दौरान पीएसबी का निवल लाभ 1.46 लाख करोड़ रुपये रहा है।

वित्तीय स्थिति में सुधार होने से बैंक बेहतर ऋण उपलब्धता, नीतिगत ब्याज दरों के बेहतर संचरण, जमाकर्ता के बढ़े हुए विश्वास और डिजिटल तथा वित्तीय सेवाओं की व्यापक पहुंच के माध्यम से आम ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। ईज एजेंडा के अंतर्गत ग्राहक-केंद्रित सुधारों और प्रौद्योगिकी को अपनाने से सेवा वितरण, पारदर्शिता और बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच में भी सुधार हुआ है, जिससे खुदरा ग्राहकों, एमएसएमई और ग्रामीण आबादी को विशेष रूप से लाभ हुआ है।

(ख) और (ग): हाल ही में ऋण में सख्ती और बाजार की चिंताओं के संबंध में, एससीबी में एमएसएमई ऋण में साल-दर-साल वृद्धि जारी रही है, जो दिनांक 30.9.2025 कि स्थिति के अनुसार 20.6% रही है, और दिनांक 30.9.2025 कि स्थिति के अनुसार 3.5% की दर से सकल एनपीए के साथ आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो व्यापक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव की अनुपस्थिति को दर्शाता है। जबकि एससीबी में खुदरा उधारकर्ताओं के संबंध में, समग्र खुदरा ऋण गुणवत्ता स्थिर बनी हुई है या उसमें सुधार हो रहा है, और दिनांक 30.9.2025 कि स्थिति के अनुसार 1.1% की दर से सकल एनपीए के साथ आस्ति गुणवत्ता में व्यापक गिरावट का संकेत नहीं देता है। व्यक्तिगत ऋण (खुदरा ऋण) में दिनांक 31.10.2025 को 14.0% की वृद्धि हुई, जो दिनांक 31.3.2025 को हुई 11.7% की वृद्धि से अधिक है।

*****